



ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

19-07-2023

द हिंदू राष्ट्रीय

⇒ विपक्ष की टीम इंडिया लोकसभा चुनाव में एनडीए से भिड़ेगी।

26 विपक्षी राजनीतिक दल ने अपने चुनाव का नाम I.N.D.I.A घोषित किया।

भारत - भारत राष्ट्रीय विकासात्मक, समावेशी गठबंधन। 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का मुकाबला करने के लिए।

सर्वसम्मत संयुक्त प्रस्ताव में संविधान में निहित "भारत के विचार" की रक्षा करने, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाजपा के "नफरत के जहरीले अभियान" से लड़ने और महिला, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने का संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना लागू की जानी चाहिए।

गठबंधन अभियान प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में एक साझा सचिवालय स्थापित करेगा।

विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी।

पीएम ने कहा, "नकारात्मकता का गठबंधन कभी सफल नहीं होता।"

पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 38 सदस्यीय एनडीए "योगदान का गठबंधन है, न कि करुणा का" इसमें भाग लेने वाली कुछ प्रमुख पार्टियां शिवसेना, एआईएडीएमके, असोम गावा पैरिशड आदि थीं।

लोक जन शक्ति पार्टी (चिराग) एनडीए गठबंधन के रूप में वापस आ गई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

⇒ भारत ने 2022 में रिकॉर्ड 93% डीपीटी3 टीकाकरण कवरेज दर्ज किया: डब्ल्यूएचओ।

डीपीटी3 (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस) वैक्सीन के लिए भारत की कवरेज दर रिकॉर्ड 93% तक बढ़ गई डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए कवरेज के लिए 2011 का अनुमान लगाया है, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का अनुमान है कि भूटान (98%) मालदीव (99%), बांग्लादेश (98%) थाईलैंड (97%) में भारत की तुलना में उसका अनुमानित टीकाकरण कवरेज अधिक है। दक्षिण - पूर्व एशिया। 2022 में इंडोनेशिया कवरेज 85% रहा।

⇒ पटरी से उतरी भारत-रूस बंदे भारत डील पटरी पर लौट आई है

मौजूदा सौदे के तहत भारतीय रेलवे की आरवीएनएल (रेल विकास निगम लिमिटेड) और रूस की मेट्रोवेओनमैश एक संयुक्त उद्यम में 120 करोड़ रुपये की लागत से 120 ट्रेनों का निर्माण करेंगी।

संयुक्त उद्यम में फंसी सफेद आरवीएसआईएल ने सौदे में 69% की बहुमत हिस्सेदारी की मांग की।

वर्तमान में आरवीएनएल और मेट्रो वैगन मैश की हिस्सेदारी क्रमशः 25% और 75% है।

⇒ सरकार ने सहारा के छोटे निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए पोर्टल खोला।

केंद्रीय गृह एवं निगम मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा समूह की कंपनियों से जुड़ी चार सहकारी समितियों के निवेशकों का समय लौटाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इस संबंध में सहारा समूह की दो कंपनियों की जांच की जा रही है।

घोटाले के बारे में

चार सहकारी समितियाँ, सहारा क्रेडिट सहकारी समिति, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्सनल, हमारा इंडिया क्रेडिट सहकारी समिति लिमिटेड और लखनऊ, भोपाल, कोलकाता और हैदराबाद में स्थित मल्टीपर्सनल सहकारी

समिति लिमिटेड को सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। 2022, बी/डब्ल्यू 2010 और 2014।

लेकिन लगभग 25,000 करोड़ के चक्कर में सहकारी समिति के सदस्यों की गाड़ी कमाई फंस गयी।

29 मार्च को SC ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से करीब 10 करोड़ निवेशकों को रिफंड देने का आदेश दिया।

लॉन्च किया गया पोर्टल 10,000 तक के दावों का निपटान करेगा और इससे निवेश किए गए लगभग 1.7 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

⇒ **पुंछ में "क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए भेजे गए 4 आतंकवादी" मारे गए।**

⇒ **सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी जांच पर रोक लगा दी**

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी से 2,000 शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में "हर तरह से अपना हाथ" रखने को कहा।

दुनिया

⇒ **चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयास के लिए ट्रम्प को दोषी ठहराया जाएगा।**

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्हें एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि वह 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पूर्ववत करने के प्रयास में न्याय विभाग की जांच का लक्ष्य हैं। एक संकेत है कि उसे जल्द ही संघीय अभियोजन द्वारा दोषी ठहराया जा सकता है।

⇒ **चुप्पी ने चीन के विदेश मंत्री के गिरोह में शामिल होने की अटकलों को हवा दी**

चीन के विदेश मंत्री गैंग की जनता से 23 दिन की अनुपस्थिति ने चीन और विदेश दोनों में त्रिपक्षीय अटकलें लगा दी हैं और जब टीआईएस नेताओं के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन की बात आती है तो बीइंग की गोपनीयता की गिनती नीति पर बहस छिड़ गई है।

श्री किन ने आखिरी बार 23 जून को श्रीलंका के समकक्ष के साथ बैठक में भाग लिया था। श्री किन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें राजनेता सदस्य वांग यी ने भाग लिया था।

पिछले सप्ताह चीनी विदेश मंत्रालय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि श्री किन "स्वास्थ्य कारणों" से पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। चीनी मंत्रालय की ओर से इस पर आगे अपडेट नहीं दिया गया है।

⇒ **ब्रिटेन का अवैध प्रवासन विधेयक कानून बनने की राह पर है।**

ब्रिटेन के हाउस टू लॉर्ड्स ने सोमवार को अवैध प्रवासन विधेयक पारित कर दिया, इससे ब्रिटेन का अवैध प्रवासन विधेयक कानून बनने के करीब पहुंच गया है।

'बोट बंद करो' पीएम सुनक की पांच प्राथमिकताओं में से एक थी। लगभग 45% शरण चाहने वाले वे हैं जो अवैध नौकाओं के साथ अंग्रेजी चैनलों को पार करके आते हैं।

विधेयक का प्रस्ताव है:

(1) शरण चाहने वालों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना। यह शरण चाहने वालों के लिए मार्ग तय करने की बात करता है।

(2) कई शरण चाहने वालों को रवांडा भेजा जाएगा: लेकिन ब्रिटेन की अदालत ने इस योजना को अवैध घोषित कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र ने यूके के नए बिल की आलोचना की है "दशकों से, यूके ने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप जरूरतमंद लोगों को शरण प्रदान की है, यह कानून उस कानूनी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है जिसने आंतरिक कानून में प्रत्येक में गंभीर जोखिम के लिए शरण लेने वाले कई शरणार्थियों की रक्षा की है" संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी फिलिप्पो ग्रांडी ने कहा।

⇒ **रूस ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह को निशाना बनाया, इसे क्रीमिया के पुल पर हमले का बदला बताया।**

रूस ने मंगलवार को हवाई सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए 25 विस्फोटक ड्रोन दागकर ओडेसा बंदरगाह पर हमला किया और बाद में छह कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागीं। यूक्रेनी सूत्रों ने कहा कि सभी छह मिसाइलों को हवाई सुरक्षा बलों ने मार गिराया।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसका "प्रतिशोध पर हमला" ओडेसा और मायकोलाइव के पास यूक्रेन की सैन्य सुविधा पर समुद्री प्रक्षेपण सटीक हथियारों के साथ किया गया था। इसने एक शिपयार्ड यूक्रेनी ईंधन डिपो सहित रूस के खिलाफ "आतंकवादी हमलों" की तैयारी को नष्ट कर दिया।

⇒ **अमेरिकी सैनिक जो उत्तर कोरिया की सीमा पार कर गया।**

हम। सैनिक जो उत्तर कोरिया की सीमा पार कर गया

माना जाता है कि एक अमेरिकी सैनिक को उत्तर कोरिया द्वारा भारी किलेबंदी वाली सीमा पार करने के बाद हिरासत में लिया गया है, इससे दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो सकते हैं।

⇒ **डीआर कैंगो की सरकारी कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 1.9 बिलियन खनन समझौते पर हस्ताक्षर किए।**

सम्पादकीय-1

चयनात्मक उत्पीड़न

जांच एजेंसियों को अपनी जांच पर राजनीति का रंग नहीं चढ़ने देना चाहिए।

संपादकीय आखिर किस बारे में है?

संपादकीय तमिलनाडु की डीएमके सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री पर ईडी के हालिया छापे के बारे में है। संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया है कि एड की जांच पर जोर देना उचित नहीं है।

के. पोनमुडी की संपत्ति पर ईडी की छापेमारी के बारे में

के. पोनमाडी तमिलनाडु में वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उनके ऊपर गंभीर बदलावों में अन्नाद्रमुक शासन के दौरान 2007 और 2011 के बीच खान और खनिज संसाधन मंत्री रहते हुए सीमा से अधिक लाल रेत उत्खनन की अनुमति देना शामिल है। उन्होंने अपने बेटे, दोस्तों और रिश्तेदारों को उत्खनन लाइसेंस देने का भी आरोप लगाया है।

⇒ **सैंथीपालजी का मामला**

इससे पहले ईडी ने एक अन्य मंत्री सैंथीबालाजी पर छापे मारा था, जिन पर एआईएडीएमके शासनकाल में परिवहन मंत्री रहते हुए भर्ती के लिए पैसे लेने का आरोप है।

इलाज के बाद सैंथिलबालाजी ईडी की हिरासत में हैं।

⇒ **संपादकीय क्या कहता है?**

संपादकीय बताता है कि लोगों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए ईडी की छापेमारी चयनात्मक नहीं होनी चाहिए।

सम्पादकीय-2

एक अनाचारवाद

राष्ट्रमंडल खेल आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने के लिए संघर्ष करेंगे
संपादकीय आखिर किस बारे में है?

⇒ **ऑस्ट्रेलिया का राज्य विक्टोरिया कॉमन वेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूए), 2023 की मेजबानी से हट गया है। संपादकीय में विक्टोरिया द्वारा दिए गए कारण के बारे में बात की गई है, और यह ऑस्ट्रेलिया और आगामी आयोजनों को कैसे प्रभावित कर सकता है।**

विक्टोरिया के CWG 2026 से हटने के फैसले के बारे में। विक्टोरिया ने 2026 CWG खेलों की मेजबानी से नाम वापस ले लिया है। उद्धृत मुद्दा वित्तीय है। प्रारंभिक अनुमानों में बजट के लिए 2.6 बिलियन का बजट अनुमानित किया गया था, हालांकि, गवर्नर डैनियल एंड्रयूज ने कहा है कि लागत 6 बिलियन से अधिक हो सकती है और संघीय वित्त पोषण के बिना 12 दिवसीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए लागत बहुत अधिक है और विक्टोरिया संघर्ष कर रही है। इसके बढ़ते कर्ज के बारे में उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए अस्पतालों और स्कूलों से पैसा नहीं ले सकते।

⇒ **यह खेल आयोजन के मेजबान देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को कैसे प्रभावित कर सकता है।**

प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बुनीज़ मेजबानी के लिए उत्सुक हैं। 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप और 2032 ओलंपिक की तैयारी जिसकी मेजबानी ब्रिस्बेन करेगा।

इतने बड़े आयोजन के बावजूद, इसे ऑस्ट्रिया के लिए मेयर के सम्मान के रूप में गिना जाएगा जिसने 2018 में इसकी मेजबानी की थी (गोल्ड कोस्ट)